

64

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : - तीन -दतिया/भू०रा०/2018/0093 विरुद्ध - आदेश
दिनांक 13-11-2017 पारित द्वारा - अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग,
ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 599/2012-13 अपील

गोपाल शर्मा पुत्र कमलेश शर्मा

निवासी ग्राम थरेट तहसील सेवड़ा

जिला दतिया मध्य प्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

लखनलाल शर्मा पुत्र रघुवीरशरण शर्मा

निवासी ग्राम थरेट तहसील सेवड़ा

जिला दतिया मध्य प्रदेश

—अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 8-2-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक
599/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवड़ा के
समक्ष ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30-6-2006 के
विरुद्ध अपील क्रमांक 64/2008-09 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम थरेट स्थित भूमि सर्वे

क्रमांक 686 रकबा 1-254 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) रघुवीरशरण पुत्र दुर्गाप्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। रघुवीर शरण के पुत्र लखनलाल, कमलेश कुमार व पत्नि सियारानी वारिसान है। कमलेश कुमार का आवेदक पुत्र है। वादग्रस्त भूमि रघुवीर शरण एवं गोपाल पुत्र कमलेश के नाम से वर्ष 2007-08 में नामान्तरण पंजी क्रमांक 43 व आदेश दिनांक 30-6-06 से बटवारा अंकित हुआ है। रघुवीरशरण की भूमि में जब गोपाल शर्मा सहखातेदार अंकित नहीं था, तब पारिवारिक बटवारा कराने का पात्र नहीं है। इसलिये ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30-6-2006 को निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी सेवदा ने प्रकरण क्रमांक 64/2008-09 अपील पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-5-2013 पारित करके अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी सेवदा के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 599/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 से अनुविभागीय अधिकारी सेवदा का आदेश दिनांक 16-5-2013 एवं ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30-6-2006 से किया गया बटवारा निरस्त कर भूमि को शासकीय अभिलेख में बटवारे के पूर्व स्थिति में अंकित करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वादग्रस्त भूमि को उसके बाबा (Grand father) ने 1/2 भाग अर्थात् 0.627 आरे का अपनी इच्छा से स्वयं के नाती (Grand son) के हित में नामान्तरण पंजी पर दिनांक 30-6-06 से नामांतरित कराई है शेष 0.627 आरे उसके बाबा रघुवीरशरण के नाम बनी रही। रघुवीरशरण की मृत्यु दिनांक 8-5-2007 को होने के बाद उनके नाम की भूमि पर वारिसान के नाम समान भाग पर

विधिवत् नामान्तरण हुआ है जिस पर अनावेदक लखनलाल शर्मा के भी हस्ताक्षर हैं। रघुवीरशरण की मृत्यु के बाद आदेश दिनांक 15-8-07 से वारिसान के हुये नामान्तरण के कारण लखनलाल शर्मा को नामान्तरण पंजी पर हुई प्रविष्टि दिनांक 25-5-06 आदेश दिनांक 30-6-06 की जानकारी रही है इसके बाद भी जमीन हड़पने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 30-6-06 के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 5-2-09 को अनुविभागीय अधिकारी सेवदा के समक्ष अपील की गई है जो सही कारणों से निरस्त की गई है। जब अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील हुई, अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को शोचे समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश से अनुविभागीय अधिकारी सेवदा के आदेश दिनांक 16-5-2013 को एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30-6-2006 को निरस्त करते हुये बटवारा निरस्त कर भूमि को शासकीय अभिलेख में बटवारे के पूर्व स्थिति कायम कराने में भूल की गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम थरेट स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 686 रकबा 1-254 हैक्टर उसके पिता के नाम से थी। उनके वारिसान लखनलाल, कमलेश कुमार व पत्नि सियारानी है कमलेश कुमार का आवेदक गोपाल शर्मा पुत्र है परन्तु आवेदक ने हलका पटवारी से मिलकर खसरे में प्रविष्टि कराई है एंव बटवारे की सूचना अनावेदक को नहीं दी है। मृतक पिता रघुवीरशरण की संपूर्ण 1-254 हैक्टर में उसका अन्य वारिसान की तरह समान हिस्सा है परन्तु अपर आयुक्त ने स्थिति के बाहर जाकर समान बटवारा न करते हुये आदेश पारित किया है इसलिये मृतक रघुवीरशरण के समस्त वारिसानों के नाम वादग्रस्त भूमि के नामांतरण के आदेश दिये जाँय।


5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सेवदा के प्र०क्र० 64/2008-09 अपील में पृष्ठ क्रमांक 20 पर तहसीलदार सेवदा का पत्र क्रमांक क्यू/प्रतिलिपि शाखा/09 दिनांक 22-1-09 संलग्न है जिसमें अंकित है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30-6-2006 से किये गये नामान्तरण की पंजी रिकार्ड

रूम में नहीं है क्योंकि यह पंजी रिकार्ड में जमा नहीं हुई है। जहां तक नामान्तरण पंजी पर किये गये रघुवीरशरण शर्मा एवं गोपाल पुत्र कमलेश शर्मा के बीच भूमि सर्वे क्रमांक 686 रकबा 1-254 हैक्टर के बटवारा किये जाने का प्रश्न है ? विभाजन के लिये म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में इस प्रकार का प्रावधान है -

1. धारा 178 (1) - यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।
2. म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०) - धारा 178 विभाजन की कार्यवाही नामान्तरण पंजी पर नहीं की जा सकती। तहसीलदार के लिये आवेदन देना अनिवार्य है।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 13-11-2017 के पद 6 में की गई विवेचना एवं निकाले गये निष्कर्षों के अवलोकन से परिलक्षित कि अपर आयुक्त द्वारा वादग्रस्त भूमि के किये गये बटवारा एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म्याद अधिनियम के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष सही नहीं पाये गये है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 13-11-2017 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये भूमि को पूर्व स्थिति में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का उचित निर्णय लिया है। यदि पक्ष विशेष वादग्रस्त भूमि में मृतक रघुवीरशरण द्वारा छोड़ी की वादग्रस्त भूमि में स्वत्व चाहते है तब वह व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराने हेतु वह स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र०क्र० 599/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दि. 13 नवम्बर, 2017 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 599/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।


(एस०एस०अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर